साप्ताहिक करंट अफेयर्स 12-17 जुलाई 2021

Important News: State

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य (टाइगर रिजर्व) नामित

चर्चा में क्यों?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य में बदलने की मंजूरी दे दी है।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** की तकनीकी समिति ने हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी।
- यह देश का 52 वां बाघ अभयारण्य होगा।

प्रमुख बिंदु

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में 1,071 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
- **अन्य तीन हैं - रणथंभौर टाइगर रिजर्व** सवाई माधोपुर में, **सरिस्का टाइगर रिजर्व** अलवर में, और **मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व** कोटा में।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के बारे में:

- **NTCA** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के** प्रावधानों के तहत किया गया था, 2006 में संशोधित।

प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में:

- प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश में बाघों के संरक्षण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती है।

वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- एक ऐसा क्षेत्र जहां जानवरों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास के तहत संरक्षित और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से संरक्षित किया जाता है, वन्यजीव अभयारण्य कहलाता है।
- भारत में 553 वन्यजीव अभयारण्य हैं (राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस, दिसंबर 2019)।

भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन

चर्चा में क्यों?

- **उत्तराखंड के देहरादून जिले के चकराता शहर** में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

क्रिप्टोगेमिक गार्डन के बारे में:

- लाइकेन, फर्न और कवक की लगभग 50 प्रजातियां 9,000 फीट की कमांडिंग ऊंचाई पर चकराता के देवबन में बगीचे में उगाई गई है।
- इस स्थान को देवबन में इसके निम्न प्रदूषण स्तर और नम परिस्थितियों के कारण चुना गया है जो इन प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल हैं।
- देवबन में देवदार और ओक के प्राचीन राजसी जंगल हैं जो क्रिप्टोगैमिक प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास बनाते हैं।

क्रिप्टोगेम:

- क्रिप्टोगेम का अर्थ है "अदृश्य प्रजनन" इसका अभिप्राय यह है कि वे किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं।
- शैवाल, ब्रायोफाइट्स (मॉस, लिवरवॉर्ट्स), लाइकेन, फ़र्न और कवक क्रिप्टोगेम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जयपुर को मिलेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम

चर्चा में क्यों?

- **भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)** ने **राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA)** को 100 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान जारी किया, जिसका उपयोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए किया जाएगा।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- यह **दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा**।

प्रमुख बिंदु

- नए स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और इसे दो चरणों में बनाया जाएगा।
- **पहला** सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम - **नरेंद्र मोदी स्टेडियम** अहमदाबाद में स्थित है जबकि **दूसरा** सबसे बड़ा स्टेडियम **ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न** में स्थित है।
- **नोट:** फरवरी, 2021 में, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया था, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया।

Important News: India

न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं का विकास

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने **न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास** के लिए **केन्द्र प्रायोजित योजना** को कुल 9,000 करोड़ रुपये की लागत में 01 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक और पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिये **ग्राम न्यायालय योजना** तथा **न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मिशन** के ज़रिये मिशन मोड में 50 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन (NMJDLR) के बारे में:

- इसे 2011 में दोहरे लक्ष्यों के साथ शुरू किया गया था। पहला देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाना है और दूसरा संरचनात्मक परिवर्तन और प्रदर्शन मानकों को स्थापित करके जवाबदेही बढ़ाना है।
- न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना 1993-94 से चल रही है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- इस प्रस्ताव से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 3800 कोर्ट हॉल और 4000 आवासीय इकाइयों (नई और वर्तमान में चल रही, दोनों किस्म की परियोजनाओं), वकीलों के लिए 1450 हॉल, 1450 शौचालय परिसरों और 3800 डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण में मदद मिलेगी।

ग्राम न्यायालय:

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों को प्रमाणित करके ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने के निर्णय को भी मंजूरी दी।
- **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008,** जोकि 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ था, को देश के ग्रामीण इलाकों में न्याय प्रणाली तक त्वरित और आसान पहुंच बनाने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए लाया गया था।

योजना की निगरानी

- न्याय विभाग द्वारा *एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली* स्थापित की गई है जो प्रगति, निर्माणाधीन कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के पूरा होने से संबंधित डेटा संग्रह के साथ-साथ बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन को संभव बनाती है।
- न्याय विभाग ने ISRO की तकनीकी सहायता से एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है।
- उन्नत वेब पोर्टल **"न्याय विकास-2.0"** और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग CSS न्यायिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।
- **ग्राम न्यायालय पोर्टल** इस योजना को लागू करने वाले राज्यों द्वारा ग्राम न्यायालयों के कामकाज की ऑनलाइन निगरानी में मदद करता है।

स्रोत: PIB

सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA 17% से बढ़ाकर 28% किया

चर्चा में क्यों?

- कैबिनेट ने 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- इसके साथ ही DA की नई दर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- देश में महामारी की चपेट में आने के कारण 2020 में DA और DR फ्रीज़ कर दिए गए थे।
- 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच की अवधि के लिए DA की दर 17 प्रतिशत रहेगी।

महंगाई भत्ते (DA) के बारे में:

- महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई और भत्ते की गणना है।
- DA साल में दो बार संशोधित किया जाता है - एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

मंत्रिमंडलीय समितियां

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

मंत्रिमंडलीय समिति के बारे में:

i. राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
ii. रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति
iii. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
iv. संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
v. निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति
vi. सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
vii. आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
viii. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति

gradeup
Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सभी समितियों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता हैं।
- इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन, रूल ऑफ बिज़नेस उनकी स्थापना के लिए प्रावधान करता है।
- कार्यकारी भारत सरकार (GoI) व्यावसायिक नियम, 1961 के लेनदेन के तहत काम करता है।
- ये व्यावसायिक नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) से प्रेरित हैं।

उद्देश्य:

- मंत्रिमंडलीय समितियां मूल रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल के भीतर उप-समितियां हैं जो विशिष्ट प्रेषणों को देखती हैं और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करती हैं, और यहां तक कि संसद सत्रों की तारीखों पर निर्णय लेती हैं।

मंत्री समूह (GoM):

- विभिन्न मुद्दों को देखने के लिए मंत्रिमंडलीय समितियों के अलावा, कई मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया गया है।
- ये तदर्थ निकाय हैं जिन्हें मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने या सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया हो सकता है।

स्रोत: द हिंदू

Important News: World

शेर बहादुर देउबा ने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

- नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
- **नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी** ने शेर बहादुर देउबा को पद की शपथ दिलाई।
- **नोट:** शेर बहादुर देउबा को संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो उनके लिए शपथ लेने के 30 दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना अनिवार्य बनाता है।

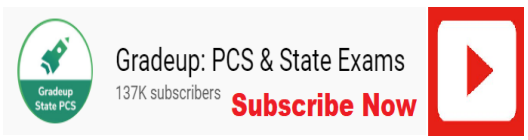

- उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 4 कार्यकाल (1995-1997, 2001–2002, 2004–2005 और 2017–2018) में कार्य किया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

वियतनाम ने भारत में पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया

चर्चा में क्यों?

- वियतनाम ने बेंगलुरु स्थित **एनएस श्रीनिवास मूर्ति को कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत** नियुक्त किया है।
- वह **भारत से वियतनाम** के **पहले** और दुनिया भर में 19वें **मानद महावाणिज्य दूत** हैं।
- नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए है।

प्रमुख बिंदु

- **मानद महावाणिज्य दूत** वियतनाम और कर्नाटक राज्य के बीच व्यापार, अर्थशास्त्र, निवेश, पर्यटन, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- उद्योगपति श्री मूर्ति एनके सुब्बैया सेट्टी एंड संस के मालिक और प्रबंध भागीदार हैं, जो 1932 से अगरबत्ती के निर्माण में है।

भारत-वियतनाम संबंध:

- दोनों देशों ने अपने **राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ** को चिह्नित करने के लिये **वर्ष 2022** में विभिन्न स्मारक गतिविधियों हेतु सहमति व्यक्त की है।
- वियतनाम और भारत, भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडो-पैसिफिक पर ASEAN के आउटलुक के अनुरूप अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं।
- वियतनाम और भारत संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व व्यापार संगठन के अलावा ASEAN, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों में एक-दूसरे को घनिष्ट रूप से सहयोग करते हैं।
- ASEAN -भारत मुक्त व्यापार समझौता
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग
- भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी
- सैन्य अभ्यास: VINBAX, IN-VPN BILAT

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

वियतनाम के बारे में तथ्य:

- **राजधानी:** हनोई
- **मुद्रा:** वियतनामी डोंग
- **राष्ट्रपति:** गुयेन जुआन फुक
- **प्रधानमंत्री:** फाम मिन्ह चिन्ह

स्रोत: द हिंदू

प्रथम भारत-UK वित्तीय बाजार संवाद

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने **भारत-UK वित्तीय बाजार संवाद ("संवाद")** की उद्घाटन बैठक की।

प्रमुख बिंदु

भारत-UK वित्तीय बाजार संवाद के बारे में:

- संवाद का नेतृत्व भारतीय वित्त मंत्रालय और HM ट्रेजरी के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।
- संवाद की शुरुआत सरकारों के बीच चर्चा के साथ हुई, जो चार विषयों पर केंद्रित थी:

(1) GIFT (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी, भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र

(2) बैंकिंग और भुगतान

(3) बीमा

(4) पूंजी बाजार

- बैठक में भारतीय और UK के प्रतिनिधियों ने **UK-इंडिया GIFT सिटी रणनीतिक साझेदारी** की प्रगति पर चर्चा की।
- दोनों पक्षों ने आगे और सहयोग पर रजामंदी व्यक्त की, जिसमें सतत वित्त और फिन-टेक को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य UK के उद्योगों की उपस्थिति बढ़ाने की प्रक्रिया को समर्थन देना है।
- वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में **10वीं आर्थिक और वित्तीय संवाद (EFD)** में **संवाद** स्थापित किया गया था।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- वित्तीय सहयोग दो प्रधानमंत्रियों की हाल ही में बैठक के दौरान **दोनों देशों द्वारा अपनाए गए 2030 रोडमैप** के प्रमुख स्तंभों में से एक है और भारत-UK वित्तीय बाजार संवाद इस वित्तीय सहयोग के प्रमुख तत्वों में से एक है।

भारत-UK व्यापार के बारे में:

- 2007 में पहली EFD के बाद से भारत-UK व्यापार दोगुने से अधिक हो गया है, जिसमें द्विपक्षीय निवेश से दोनों देशों में आधे मिलियन से अधिक नौकरियों का समर्थन हुआ है।
- भारत-UK आर्थिक संबंध एक साथ महत्वपूर्ण हैं, वे दुनिया की शीर्ष सात अर्थव्यवस्थाओं में से दो हैं, जिनका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।

स्रोत: PIB

1. STI के नेतृत्व वाली BRICS नवाचार सहयोग कार्य योजना

चर्चा में क्यों?

- **BRICS विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक** के दौरान **भारत** द्वारा प्रस्तावित **STI के नेतृत्व वाली BRICS नवाचार सहयोग कार्य योजना (2021-24)** पर सभी BRICS देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
- **भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** ने BRICS विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक की मेजबानी की थी।

प्रमुख बिंदु

STI के नेतृत्व वाली BRICS नवाचार सहयोग कार्य योजना के बारे में:

- भारत ने एक-दूसरे के नवाचार परिवेश के अनुभवों को साझा करने और अनूठी पहल करने वालों एवं उद्यमियों को एक दूसरे से जोड़ने की सुविधा के लिए इस योजना का प्रस्ताव रखा था।
- **BRICS विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार उद्यमशीलता सहयोग कार्यबल** द्वारा इस कार्य योजना का विवरण तैयार किया जाएगा।

विषयगत क्षेत्र:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- BRICS अधिकारियों ने बैठक में इस वर्ष के प्रस्तावों के लिए विषयगत क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की और दस विषयगत क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।
- सभी देश **BRICS युवा वैज्ञानिक सम्मेलन** के **छठे संस्करण** के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित विषयगत क्षेत्रों पर सहमत हुए। यह सम्मेलन इस वर्ष **13-16 सितंबर 2021 के दौरान बंगलूरु** में आयोजित किया जाएगा।
- सम्मेलन में जिन तीन विषयों पर चर्चा की जाएगी उनमें **स्वास्थ्य देखरेख, ऊर्जा समाधान, साइबर-भौतिक प्रणाली,** और उनके अनुप्रयोग।

- **नोट: 13 वां BRICS शिखर सम्मेलन** 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जाएगा, और 2012 और 2016 के बाद तीसरी बार भारत BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

- 2021 के लिए भारत की अध्यक्षता का विषय **'BRICS @ 15: इंट्रा- BRICS कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेन्सस'** होगा।
- **BRICS के बारे में तथ्य:**

  स्थापना: 2009

  देश: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका

BRICS दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है, जिसमें शामिल हैं:

- अरब लोगों के साथ विश्व की 41% आबादी
- विश्व की कुल भूमि सतह का 29.3% का कुल संयुक्त क्षेत्र
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24%
- विश्व व्यापार का 16%

नोट: उपरोक्त डेटा विश्व बैंक डेटा (2019) पर आधारित है।

स्रोत: PIB

Important News: Economy

NTPC की नई सौर परियोजनाएं

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

चर्चा में क्यों?

- **NTPC की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड** ने इस क्षेत्र में **देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना (ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट)** स्थापित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- MoU पर हस्ताक्षर को लेह में सोलर ट्री और सोलर कार पोर्ट के रूप में **NTPC के पहले सोलर इंस्टॉलेशन** के उद्घाटन के साथ भी चिह्नित किया गया था।
- NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड **गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क** स्थापित करेगी। यह **भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा**।

प्रमुख बिंदु

हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना:

- समझौता ज्ञापन NTPC को अक्षय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन के आधार पर लद्दाख को कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करेगा।
- NTPC ने इस क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसें चलाने की योजना बनाई है। कंपनी लेह में एक सौर संयंत्र और एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई भी स्थापित करेगी।
- इससे लेह हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन जाएगा।

भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क:

- NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड **अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क योजना** के तहत **गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क** स्थापित करेगी। यह **भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा**।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को यह मंजूरी सोलर पार्क योजना के मोड 8 (अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क) के तहत दी है।

- NTPC आरईएल की इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की योजना है।

NTPC के बारे में:

- NTPC लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न PSU है।

NTPC लक्ष्य:

- NTPC ने हाल ही में 2032 तक 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को संशोधित किया है, जो पिछले लक्ष्य को लगभग दोगुना कर देता है।

NTPC की परियोजना:

- हाल ही में, NTPC ने विशाखापत्तनम में भारत की 10 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू की है।
- तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।

अन्य सौर ऊर्जा पहल:

राष्ट्रीय सौर मिशन:

- यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक पहल है।
- यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की कई नीतियों में से एक है।
- कार्यक्रम का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 11 जनवरी 2010 को 2022 तक 20 गीगावाट के लक्ष्य के साथ किया था।
- इसे बाद में भारत के 2015 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस (ISA) के बारे में:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- ISA को भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, या COP21 के दौरान पेरिस में लॉन्च किया गया था।
- **मुख्यालय:** गुरुग्राम, हरियाणा, भारत
- **स्थापना:** 30 नवंबर 2015

स्रोत: PIB

भूटान में BHIM-UPI

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भूटान के अपने समकक्ष माननीय वित्त मंत्री श्री ल्यिन्पो नामगे शेरिंग के साथ संयुक्त रूप से भूटान में BHIM-UPI का शुभारंभ किया।
- **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम** की शाखा, **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)** ने BHIM-UPI को भूटान में लागू करने के लिए **भूटान की रॉयल मॉनीटरी अथॉरिटी (RMA)** के साथ भागीदारी की है।

प्रमुख बिंदु

- **भूटान अपने QR के उपयोग के लिए UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश** है और BHIM ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला हमारा पहला निकट पड़ोसी देश है।

लाभ:

- भूटान में BHIM-UPI की शुरूआत के साथ दोनों देशों की भुगतान संबंधी अवसंरचना सुचारू रूप से आपस में जुड़ गई हैं और इससे हर साल भूटान की यात्रा करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ होगा।
- **BHIM-UPI** भारत की प्रगति के सबसे उज्ज्वल पड़ावों में से एक है और COVID-19 महामारी के काल में डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले पांच वर्षों में 100 मिलियन से अधिक UPI QR बनाए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान BHIM-UPI ने 41 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 22 अरब लेनदेन को पूरा करने में योगदान किया है।

BHIM के बारे में:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- यह **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस** पर आधारित **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** द्वारा विकसित एक भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बारे में:

- यह एक तत्काल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है, जो उपयोगकर्ताओं को कई बैंक खातों में वास्तविक समय के आधार पर धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है।

नोट: भारत और भूटान एक दूसरे के यहां में **RuPay कार्डों** की स्वीकृति के अंतर-संचालन को दो चरणों में - पहले चरण में भारत में जारी RuPay कार्डों की भूटान स्थित टर्मिनलों पर स्वीकृति और दूसरे चरण में इन कार्डों की उल्टे क्रम में स्वीकृति - संभव बना चुके हैं।

RuPay के बारे में:

- यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा और भुगतान सेवा प्रणाली है, जिसे 26 मार्च 2012 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा परिकल्पित और लॉन्च किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के बारे में:

- यह भारत में RBI के स्वामित्व के तहत खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है।
- दिसंबर 2008 में स्थापित, NPCI **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8** के तहत पंजीकृत एक **गैर-लाभकारी संगठन** है।

स्रोत: PIB

भारत को उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समीक्षा बैठक

चर्चा में क्यों?

- **केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया** ने उर्वरकों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए **उर्वरक विभाग** की पहल की समीक्षा की।
- सरकार वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **बाजार विकास सहायता नीति** को उदार बनाने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु

बाजार विकास सहायता (MDA) नीति के बारे में:

- बाजार विकास सहायता (MDA) नीति पहले केवल शहरी खाद तक ही सीमित थी।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- इसमें जैविक कचरे जैसे बायोगैस, हरित खाद, ग्रामीण क्षेत्रों की जैविक खाद, ठोस/तरल घोल आदि को शामिल कर इस नीति के विस्तार करने की जरूरत थी।
- यह विस्तार भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान (SBA) का पूर्ण रूप से पूरक साबित होगा।

भारत में उर्वरक की खपत:

- FY20 में भारत की उर्वरक खपत लगभग 61 मिलियन टन थी - जिसमें से 55% यूरिया थी - और अनुमान है कि FY21 में 5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

सरकारी पहल और योजनाएं:

- नई निवेश नीति- 2012
- नई यूरिया नीति 2015
- यूरिया की नीम कोटिंग
- शहरी खाद के प्रचार पर नीति
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना
- उर्वरक क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग

स्रोत: PIB

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB)

चर्चा में क्यों?

- **GIS-आधारित पोर्टल, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB)** ने अप्रैल 2021 से हर महीने अपने पृष्ठ को देखे जाने (पेज व्यू) में 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी है।

प्रमुख बिंदु

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB) के बारे में:

- **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)** ने IILB विकसित किया है।
- इसमें सभी औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित सूचनाओं की एक ही स्थान पर जानकारी – सम्पर्क, आधारभूत रचनाओं, प्राकृतिक संसाधन और इलाके, खाली भूखंडों पर प्लॉट-स्तरीय जानकारी, कार्य प्रणाली और संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- वर्तमान में IILB के पास 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में लगभग 4000 औद्योगिक पार्क हैं, जो बहुत दूर से भूमि की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए निर्णय लेने हेतु एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- इस प्रणाली को 17 राज्यों के उद्योग आधारित GIS व्यवस्था के साथ एकीकृत करके जोड़ दिया गया है ताकि वास्तविक समय के आधार पर इस पोर्टल पर जानकारियों को अद्यतन किया जा सके। **दिसंबर 2021 तक अखिल भारतीय स्तर पर एकीकरण हासिल** कर लिया जाएगा।
- देशवार **आगंतुकों** के संबंध में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में आगंतुकों की अधिकतम संख्या है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी और इंडोनेशिया आते हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के बारे में:

- यह पृथ्वी की सतह पर स्थिति से संबंधित डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने, जांचने, विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम है।
- यह एक नक्शे पर कई अलग-अलग प्रकार के डेटा दिखा सकता है, जैसे कि सड़कें, भवन और वनस्पति।
- यह किसी भी जानकारी का उपयोग कर सकता है जिसमें स्थान शामिल है।
- स्थान को कई अलग-अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे अक्षांश और देशांतर, पता, या ज़िप कोड।

स्रोत: PIB

Important News: Health

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 4607.30 करोड़ रुपये के वित्तीय व्यय के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) के बारे में:

- केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन को **आयुष मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा लागू किया जा रहा है।
- **आयुष विभाग,** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 12वीं योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लागू करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया है।
- आयुष मिशन 15 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था।

उद्देश्य: राष्ट्रीय आयुष मिशन का मूल उद्देश्य लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटक:

अनिवार्य घटक

- आयुष सेवाएं
- आयुष शैक्षणिक संस्थान
- ASU और H औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण (आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी भी)
- औषधीय पौधे

नम्य घटक

- योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र
- टेली-मेडिसिन
- सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार
- स्वैच्छिक प्रमाणन योजना: परियोजना आधारित
- मार्केट प्रमोशन, मार्केट इंटेलिजेंस और बाय बैक इंटरवेंशन

केंद्रीय कल्याण योजनाओं के बारे में:

- केंद्रीय कल्याण योजनाओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: **(i) केंद्र प्रायोजित योजनाएं, (ii) केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं।**

(i) केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS):

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- केंद्र प्रायोजित योजनाएं वे योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक परिभाषित शेयरधारिता के साथ प्रायोजित की जाती हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पुनः **दो वर्गों- कोर ऑफ कोर स्कीम्स** और **कोर स्कीम्स** में विभाजित किया जा सकता है।

कोर स्कीम्स: हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन और राष्ट्रीय आजीविका मिशन कुछ प्रमुख योजनाएं हैं।

कोर ऑफ कोर स्कीम्स: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अन्य कमजोर समूहों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना।

(ii) केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं:

- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और योजना के लिए आवश्यक बजट या वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- **उदाहरण के लिए,** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

स्रोत: PIB

भारत COVID-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण 2"

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए **23,123 करोड़ रुपये** की एक नई योजना **"भारत COVID-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण 2"** को स्वीकृति दे दी है।
- चरण- II को 01 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

पैकेज के चरण- II के बारे में:

- पैकेज के चरण-II में केंद्रीय क्षेत्र (CS) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के घटक शामिल हैं।

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य शुरुआती रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के उद्देश्य से त्वरित प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में तेजी लाना है।
- केंद्रीय अस्पतालों, AIIMS और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को COVID प्रबंधन के लिए 6,688 बिस्तरों के रिपर्पस के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को जीनोम अनुक्रमण मशीनें उपलब्ध कराकर मजबूत बनाया जाएगा।
- टेली-परामर्श की संख्या प्रति दिन 50,000 से बढ़ाकर प्रति दिन 5 लाख करने के लिए ई-संजीवनी टेली-परामर्श प्लेटफार्म के राष्ट्रीय ढांचे के विस्तार के लिए भी समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी 736 जिलों में बाल चिकित्सा इकाइयां स्थापित करना और हर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र (बाल चिकित्सा CoE) की स्थापना करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में 20,000 ICU बिस्तर बढ़ाना, जिनमें से 20 प्रतिशत बाल चिकित्सा ICU बिस्तर होंगे।
- एम्बुलेंसों के मौजूदा बेड़े को मजबूत करना– पैकेज के तहत 8,800 नई एम्बुलेंस शामिल की जाएंगी।

पैकेज के चरण-I के बारे में:

- मार्च, 2020 में, जब देश COVID-19 महामारी की पहली लहर का सामना कर रहा था, तब प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ रुपये की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भारत COVID-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज" की घोषणा की थी।

DBT-NIBMG ने ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस 'dbGENVOC' तैयार किया

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान **DBT- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (NIBMG),**

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

कल्याणी ने **ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस 'dbGENVOC'** तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

dbGENVOC के बारे में:

- यह ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट्स का ब्राउज करने योग्य ऑनलाइन डेटाबेस है और इसे मुफ्त उपलब्ध कराया गया है।
- यह एक उचित सीमा तक सांख्यिकीय एवं जैव सूचनात्मक विश्लेषण को ऑनलाइन करने की भी अनुमति देता है जिसमें ओरल कैंसर में संबद्ध परिवर्तित मार्ग में वेरिएंट की पहचान करना शामिल है।

भारत में कैंसर:

- विश्व कैंसर रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2018 में भारत में अनुमानित 1.16 मिलियन नए कैंसर के मामले थे।
- भारत में 6 सबसे आम कैंसर प्रकार हैं मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़े का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और पेट का कैंसर।

ओरल कैंसर भारत में पुरुषों में पाया जाने वाला कैंसर का सबसे प्रचलित रूप है जो मुख्य रूप से तंबाकू चबाने के कारण होता है।

- तंबाकू चबाने से ओरल कैविटी में कोशिकाओं की आनुवंशिक सामग्री में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन (म्यूटेशन) ओरल कैंसर का कारण बनते हैं।

अन्य संबंधित पहलें:

- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)
- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG)
- राष्ट्रीय जीनोमिक ग्रिड (NGG)

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (NIBMG) के बारे में:

- यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।
- यह भारत में पहला संस्थान है जो स्पष्ट रूप से बायोमेडिकल जीनोमिक्स में अनुसंधान, प्रशिक्षण, अनुवाद और सेवा और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित है।

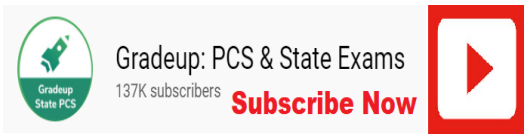

Important News: Defense

स्पर्श (SPARSH) [सिस्टम फ़ॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा)]

चर्चा में क्यों?

- **रक्षा मंत्रालय (MoD)** ने एक वेब-आधारित प्रणाली स्पर्श [सिस्टम फ़ॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा)] लागू की है।

प्रमुख बिंदु

स्पर्श के बारे में:

- यह रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है।
- यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में जमा करती है।
- इसने उन पेंशनभोगियों को अंतिम छोर से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की है जो किसी भी कारण से सीधे स्पर्श पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ हों।
- रक्षा लेखा विभाग के कई कार्यालयों के अलावा, जो पहले से ही पेंशनभोगियों के लिए सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, रक्षा पेंशनभोगियों से संबंधित दो सबसे बड़े बैंकों-भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को सेवा केंद्र के रूप में साझा तौर पर चुना गया है।

अन्य पहल:

वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना: OROP का तात्पर्य है कि समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर ध्यान दिए बिना समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB

भारतीय सेना ने सैन्य फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

चर्चा में क्यों?

- भारतीय सिनेमा में विद्या बालन के अभूतपूर्व योगदान की मान्यता में, भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री के नाम पर रखा है।
- **विद्या बालन फायरिंग रेंज गुलमर्ग, कश्मीर में स्थित** है।

प्रमुख बिंदु

- विद्या बालन हिन्दी सिनेमा की एक भारतीय अभिनेत्री हैं।
- वह एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और छह फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं।
- उन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

नोट: विद्या बालन को हाल ही में ऑस्कर के शासी निकाय, **एकेडेमी ऑफ़ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज** के बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

स्रोत: इकोनॉमिक्स टाइम्स

Environment

MoEFCC ने पर्यावरणीय उल्लंघन से निपटने के लिए SOP जारी किया

चर्चा में क्यों?

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** ने पर्यावरण उल्लंघन संबंधी मामलों से निपटने के लिये **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** जारी की।
- SOP **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)** के आदेशों का एक परिणाम है, जिसने 2021 की शुरुआत में मंत्रालय को हरित उल्लंघन के लिए दंड और एक SOP लगाने का निर्देश दिया था।

प्रमुख बिंदु

SOP हरित उल्लंघन की दो श्रेणियों को संदर्भित करता है:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- **'उल्लंघन'** में ऐसे मामले शामिल हैं जहां एक मौजूदा परियोजना के विस्तार सहित निर्माण कार्य, परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना शुरू हो गया है;
- **'गैर-अनुपालन'** जिसमें परियोजना को पूर्व पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है, लेकिन यह अनुमोदन में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन है।
- SOP के अनुसार, जिन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी की अनुमति नहीं है, उन्हें ध्वस्त किया जाना है।
- ऐसी परियोजनाएं जो पर्यावरण कानून के अनुसार अनुमत हैं, लेकिन जिन्हें अपेक्षित मंजूरी नहीं मिली है, उन्हें बंद किया जाना है।

जुर्माना:

- उल्लंघन के मामलों में, जहां संचालन शुरू नहीं हुआ है, आवेदन दाखिल करने की तारीख तक कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।
- उन मामलों में जहां आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संचालन शुरू हो गया है, कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत और उल्लंघन की अवधि के दौरान कुल कारोबार का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

MoEFCC की अन्य संबंधित पहलें:

- 2017 में, मंत्रालय ने हरित उल्लंघनों को दंडित करने पर छह महीने की माफी योजना शुरू की थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA):

- **UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम)** EIA को " पर्यावरणीय मजबूती और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक परीक्षा, विश्लेषण और योजना बनाई गतिविधियों के आकलन" के रूप में परिभाषित करता है।
- **MoEFCC** ने **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) 2020** का एक नया मसौदा जारी किया।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986** के तहत, पहली EIA अधिसूचना 1994 में जारी की गई थी। बाद में, इसे 2006 में एक संशोधित मसौदे से बदल दिया गया।
- EIA 2020 पर मसौदा अधिसूचना 2006 से जारी सभी 55 संशोधनों और 230 कार्यालय ज्ञापनों को समेकित करने के लिए थी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के बारे में:

- NGT की स्थापना 2010 में **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010** के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी।
- नई दिल्ली ट्रिब्यूनल की बैठक का प्रमुख स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई ट्रिब्यूनल की बैठक के अन्य चार स्थान है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

देश का पहला LNG सुविधा संयंत्र

चर्चा में क्यों?

- नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने देश का पहला **LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) सुविधा संयंत्र** का उद्घाटन **नागपुर, महाराष्ट्र** में किया।
- LNG सुविधा संयंत्र **बैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह** द्वारा स्थापित किया गया है ।

प्रमुख बिंदु

LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) के बारे में:

- LNG प्राकृतिक गैस है (मुख्य रूप से मीथेन, CH4, एथेन के कुछ मिश्रण के साथ, C2H6) जिसे गैर-दबाव वाले भंडारण या परिवहन की आसानी और सुरक्षा के लिए तरल रूप में ठंडा किया जाता है।
- यह गैसीय अवस्था में (तापमान और दबाव के लिए मानक परिस्थितियों में) प्राकृतिक गैस की मात्रा का लगभग 1/600 वां हिस्सा लेता है।
- LNG गंधहीन, रंगहीन, गैर-विषाक्त और गैर-संक्षारक है।
- LNG लागत प्रभावी और स्वच्छ ईंधन है जो रसद लागत को कम करने में सक्षम है।

नोट:

- सरकार पारंपरिक ईंधन के विकल्प के रूप में इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, CNG, LNG गैस को बढ़ावा दे रही है।
- मंत्रालय ने एक नीति तैयार की है जो आयात के विकल्प को लागत प्रभावी प्रदूषण मुक्त व स्वदेशी इथेनॉल, जैव CNG, LNG और हाइड्रोजन ईंधन के विकास को प्रोत्साहित करती है।

फ्लेक्स इंजन:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- श्री गडकरी ने फ्लेक्स इंजन के बारे में बात की।
- ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं विशेषकर चौपहिया और दुपहिया वाहनों के लिए फ्लेक्स इंजन बनाना अनिवार्य करने के संबंध में तीन महीने में निर्णय लिया जाएगा।
- **'फ्लेक्स इंजन'** एक आंतरिक दहन इंजन है जो एक से अधिक ईंधन और मिश्रण पर भी चल सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और कनाडा जैसे कई देशों के पास पहले से ही है।

स्रोत: PIB

Awards and Honours

भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- कौशिक बसु वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं।
- वह 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे।
- उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया।
- वह पद्म भूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं।

हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के बारे में:

- हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है और प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है।
- इस पुरस्कार में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव शामिल है।

नोट: हाल ही में, कौशिक बसु ने नीति निर्माण पर एक नई **पुस्तक** लिखी है जिसका शीर्षक **"पॉलिसीमेकर्स जर्नल: फ्रॉम न्यू डेल्ही टू वाशिंगटन D.C."** है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

स्रोत: TOI

Books and Authors

स्व. श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी द्वारा लिखित, 'द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी'

- **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी** को राज्यसभा सांसद और प्रख्यात वकील केटीएस तुलसी की मां स्व. श्रीमती बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक 'द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी' की पहली प्रति प्राप्त हुई है।
- यह पुस्तक **IGNCA** (इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स), नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है।
- **नोट:** गुरु गोबिंद सिंह मानव रूप में सिख गुरुओं में 10वें और अंतिम थे। उन्हें 9 साल की उम्र में उनके पिता गुरु तेज बहादुर, 9वें गुरु के बाद 'गुरु गद्दी' में सिंहासन पर बैठाया गया था।

स्रोत: PIB

Sports

भारत वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा

चर्चा में क्यों?

- भारत 2026 में BWF (बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन) वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।

प्रमुख बिंदु

- यह केवल दूसरी बार होगा जब भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, हैदराबाद ने 2009 में प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी की थी।
- भारत को 2023 में सुदीरमन कप का आयोजन करना था, लेकिन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने चीन को वर्ल्ड मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार देने का फैसला किया।

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) के बारे में तथ्य:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- BWF अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त बैडमिंटन के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है।
- **मुख्यालय:** कुआलालंपुर, मलेशिया
- **स्थापना:** 5 जुलाई 1934

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

इटली ने UEFA यूरो 2020 जीता

- इटली ने **यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप** लंदन के वेम्बली स्टेडियम में जीती।
- इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया।
- यह इटली का दूसरा यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब है। पहला 1968 में था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विंबलडन चैंपियनशिप 2021

- विंबलडन चैंपियनशिप एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था जो **2021 में विंबलडन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रोकेट क्लब** में हुआ था।
- **विजेताओं की सूची:**

पुरुष एकल	महिला एकल	पुरुष युगल	महिला युगल	मिश्रित युगल

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

विजेता- नोवाक जोकोविच (सर्बिया) **उपविजेता-** माटेओ बेरेटिनी (इटली)	**विजेता-** एशले बार्टी (ऑस्ट्रेलिया) **उपविजेता-** कैरोलिना प्लिस्कोवा (चेक गणराज्य)	**विजेता-** निकोला मेक्टिक (क्रोएशिया), मेट पविक (क्रोएशिया) **उपविजेता-** मार्सेल ग्रेनोलर्स (स्पेन), होरासियो ज़ेबेलोस (अर्जेंटीना)	**विजेता-** हसीह सु-वेई (चीनी ताइपे), एलिस मर्टेंस (बेल्जियम) **उपविजेता-** वेरोनिका कुडरमेतोवा (रूस), एलेना वेस्नीना (रूस)	**विजेता-** नील स्कूप्स्की (ब्रिटेन), देसिरा क्राव्ज़िक (अमेरिका) **उपविजेता-** जो सैलिसबरी (ब्रिटेन), हैरियट डार्ट (ब्रिटेन)

- **नोट: नोवाक जोकोविच (सर्बिया)** ने अपना छठा विंबलडन खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।
- **भारतीय-अमेरिकी** टेनिस खिलाड़ी **समीर बनर्जी** ने **विंबलडन बॉयज का एकल खिताब 2021** जीता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Important Days

11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व जनसंख्या दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है।
- इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है।

प्रमुख बिंदु

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- विश्व जनसंख्या दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के शासी परिषद (UNDP) द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह 11 जुलाई 1987 को फाइव बिलियन डे में जनहित से प्रेरित था।
- **2021 का विषय** 'द इम्पैक्ट ऑफ़ द COVID-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी' है।
- अक्टूबर 2011 में, वैश्विक जनसंख्या 7 अरब होने का अनुमान लगाया गया था। इसको चिह्नित करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन "7 बिलियन एक्शन" शुरू किया गया था।
- अगले 30 वर्षों में दुनिया की आबादी में 2 अरब लोगों की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 7.7 अरब से 2050 में 9.7 अरब हो सकती है और 2100 के आसपास लगभग 11 अरब हो सकती है।

नोट: भारत में चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है।

New Appointments

LIC में अब CEO, MD होंगे; कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त

चर्चा में क्यों?

- **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC),** जो एक मेगा **इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO)** शुरू करने की तैयारी कर रहा है, में अब एक **कार्यकारी अध्यक्ष के** बजाय एक **MD (प्रबंध निदेशक)** और **CEO (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) होंगे।**

प्रमुख बिंदु

- **वित्त मंत्रालय के** तहत **वित्तीय सेवा विभाग** द्वारा **भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियमों** में संशोधन करके बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, **LIC अधिनियम, 1956** के तहत कुछ अन्य नियमों में संशोधन किया गया है।

नोट: जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार द्वारा नियुक्त MD और CEO द्वारा चलाए जाते हैं, निदेशक मंडल का नेतृत्व सरकार द्वारा चुने गए गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

वर्तमान प्रबंधन:

- वर्तमान में, LIC के शीर्ष प्रबंधन में कार्यकारी अध्यक्ष और 4 MD शामिल हैं।
- LIC के अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Obituaries

भारत के 1983 विश्व कप विजेता यशपाल शर्मा का निधन

- भारत के पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य यशपाल शर्मा का निधन हो गया।
- यशपाल शर्मा 1983 में इंग्लैंड में विश्व कप जीतने वाली कपिल देव की टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे।
- एक मध्य क्रम के बल्लेबाज, शर्मा ने 37 टेस्ट मैचों और 42 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

स्रोत: द हिंदू

हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या

- हाल ही में, हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज़ की पोर्ट-ऑ-प्रिंस में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।
- वह एक हैतियन उद्यमी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 2017 से 2021 में अपनी हत्या तक हैती के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
- नवंबर 2016 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने फरवरी 2017 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।

हैती के बारे में तथ्य: कैरेबियन में देश

राजधानी: पोर्ट-ऑ-प्रिंस

मुद्रा: हैतियन गौरदे

प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक, डॉ पी के वारियर का निधन

- आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ पी के वारियर, प्रसिद्ध आयुर्वेद उपचार केंद्र और उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेद दवाओं के निर्माता - कोट्टक्कल आर्य वैद्य शाला के प्रबंध न्यासी थे।
- डॉ वारियर को 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

स्रोत: PIB

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now